



विविध समाचार



ज्या खत्म होगी एमजीएनआरईजीए की कानूनी गारंटी? खरगे बोले-नया कानून अधिकारों पर सीधा हमला

नयी दिल्ली ०३/०१ (संवाददाता): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कांग्रेस के एमजीएनआरईजीए बचाओ संग्राम की तीन प्रमुख मांगों को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह योजना दान नहीं बल्कि एक कानूनी गारंटी है। खरगे ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार से हाल ही में पारित विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम को वापस लेने, एमजीएनआरईजीए को अधिकार-आधारित कानून के रूप में बहाल करने और काम के अधिकार और पंचायतों के अधिकार को बहाल करने की मांग करती है।

खरगे ने एक पोस्ट में कहा कि एमजीएनआरईजीए



दान नहीं है। यह एक कानूनी गारंटी है। करोड़ों सबसे गरीब लोगों को उनके अपने गांवों में काम मिला; एमजीएनआरईजीए ने भूख और संकटग्रस्त पलायन को कम किया, ग्रामीण मजदूरी बढ़ाई और महिलाओं की आर्थिक गरिमा को मजबूत किया। खरगे ने आगे आरोप लगाया कि वीबी-जी राम जी अधिनियम एमजीएनआरईजीए को अधिकार-आधारित संरचना

को नष्ट करने की धमकी देता है, क्योंकि यह गारंटीकृत कार्य को मनमानी से बदल देगा, नियंत्रण को केंद्रीकृत करेगा और ग्राम सभाओं और राज्यों को कमजोर करेगा। खरगे ने कहा कि वीबी ग्राम जी अधिनियम इसी अधिकार को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। कांग्रेस इसका विरोध करती है क्योंकि काम अब गारंटीकृत अधिकार

नहीं रहेगा, बल्कि चुनिंदा पंचायतों में केवल एक अनुमति होगी। बजट सीमित कर दिए जाएंगे, इसलिए संकट के समय में भी धन समाप्त होते ही काम भी बंद हो जाएगा। दिल्ली निधि और कार्यों का निर्णय करेगी, जिससे ग्राम सभाएं और पंचायतें अप्रासंगिक हो जाएंगी। 60 दिनों के काम पर रोक से संकट के चरम समय में काम से इनकार करना वैध हो जाएगा। मजदूरी एक संरक्षित अधिकार होने के बजाय अनिश्चित और दमनीय हो जाएगी। राज्यों को 40 प्रतिशत निधि प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिससे संघवाद कमजोर होगा और गरीब राज्यों को नुकसान होगा। प्रायोगिक बायोमेट्रिक और ऐप-आधारित बाधाओं के माध्यम से श्रमिकों को बाहर कर देंगे। ग्राम संपत्तियों को

डेकेदार शैली की परियोजनाओं से बदल दिया जाएगा। खरगे ने कहा कि एमजीएनआरईजीए पर हमला करोड़ों श्रमिकों और उनके संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। हम हर पंचायत से लेकर संसद तक शांतिपूर्ण और दृढ़ता से इसका विरोध करेंगे। यह घोषणा कांग्रेस द्वारा नवगठित वीबी-जी राम जी विधेयक के खिलाफ एमजीएनआरईजीए बचाओ शीर्षक से तीन चरणों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा के बाद आई है। नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस महासचिव केशी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर रोजगार गारंटी योजना को केंद्रीकृत करने का प्रयास करने और मनमानी करने का आरोप लगाया।

अब बुजुर्गों को नहीं लगाने पड़ेंगे अस्पतालों के चक्कर, घर पर ही मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

पटना ०३/०१ (संवाददाता): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के सातवें निश्चय 'सबका सज्मान-जीवन आसान' के तहत अब राज्य के बुजुर्गों को घर बैठे आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को यह जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 24 नवंबर 2005 को राज्य में जब से हमलोगों की सरकार बनी तब से न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर



चलते हुए हमलोगों ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के उत्थान एवं हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। हमलोगों ने पूरे बिहार को अपना परिवार माना है और सबके मान और सज्मान का पूरा ज्वाल रखा है। अब राज्य में समाज के हर वर्ग के लोग सज्मान के साथ आसानी से जीवन व्यतीत कर सकें इसे लेकर हमलोगों ने

गंभीरता से कार्य प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वर्ष 2025 से 2030 के लिए राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय 'सबका सज्मान-जीवन

आसान' (इज ऑफ लिविंग) का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा उनके जीवन को और भी आसान बनाना है।

सीएम नीतीश ने कहा कि सबसे पहले हमलोगों की कोशिश है कि राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को जरूरत के समय उनके घर पर ही अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसके लिए सबसे पहले नर्सिंग सहायता की सुविधा घर पर सुहैया कराई जाएगी। साथ ही, पैथोलॉजी जांच जैसे जलड टेस्ट भी घर पर ही किए जा सकेंगे। जलड प्रेशर की जांच और ईसीजी जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी अब बुजुर्गों के घर पहुंचकर उपलब्ध होंगी। फिजियोथेरेपी की

सुविधा भी घर पर दी जाएगी। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में सभी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता तुरंत घर पर पहुंचाई जाएगी।

सीएम नीतीश ने आगे कहा कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित उपरोक्त सभी सुविधाएं उन्हें घर पर ही मिल सकें, इसे लेकर हमलोगों ने स्वास्थ्य विभाग को तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु और ज्या-ज्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसे चिह्नित किया जाना भी आवश्यक है। इस संबंध में अगर आप कोई विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव निम्न में से किसी एक माध्यम से दे सकते हैं।

घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने शुरू की सर्जिकल स्ट्राइक, गांवों-शहरों-गलियों में धरपकड़ हुई तेज

लखनऊ ०३/०१ (संवाददाता): उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करने जा रही है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और सुदृढ़ होगी, वहां दूसरी ओर प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। इस निर्णय से पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। बयान के मुताबिक उग्र सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निरुद्ध केंद्र में रखेगी, इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था अभेद होगी, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। सरकार के सख्त कदम से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर



एक सकारात्मक असर पड़ेगा। यह कदम अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को आसान बनाएगा। प्रदेश में अपराधों की संख्या कम होगी और इसके साथ ही लोगों का विश्वास भी सरकार का कार्यप्रणाली पर बढ़ेगा। बयान के अनुसार प्रदेश में घुसपैठियों की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्र लोग भी उठे रहे हैं। ऐसे में इनकी पहचान होने से सरकारी योजनाओं का लाभ असली हकदारों तक पहुंचेगा। इससे पहले, उग्र प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से अपील की थी कि वे सतर्क रहें और घरेलू अथवा

व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले उसकी पहचान अवश्य सत्यापित करें। योगी ने कहा कि उग्र प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त एवं निर्णायक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा, "उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि

घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध सघन अभियान शुरू किया गया है तथा सभी शहरी स्थानीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया

गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोलन हटाना आवश्यक है और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को वंचितों तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकता, इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और पहचाने गए घुसपैठियों को आगे की कार्रवाई के लिए निरुद्ध केंद्र भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मंडल में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जिनसे अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घरेलू या व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले उसकी पहचान अवश्य सत्यापित करें। उन्होंने कहा, राज्य की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि की नींव है। हम आपको याद दिला दें कि उच्चतम न्यायालय ने भारत में रह रहे रोहिंग्या को लेकर कानूनी स्थिति पर सवाल उठाते हुए दो दिसंबर को पूछा था कि जब देश के अपने नागरिक ही गरीबी से जूझ रहे हैं, तो घुसपैठियों को लाल कालीन बिछाकर स्वागत क्यों दिया जाए।

उमर खालिद, शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को फैसला सुनाएगा

नयी दिल्ली ०३/०१ (संवाददाता): भारत का सर्वोच्च न्यायालय 5 जनवरी को कार्यकर्ता उमर खालिद, विद्वान शरजील इमाम और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए) के तहत 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन वी अंजारी की पीठ उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें फरवरी 2020 की हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और आरोपियों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 10 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल



सिबल, अधिवक्ता सिंहवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुशीद और सिद्धार्थ लूथरा ने आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया। उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर भारत के आतंकवाद विरोधी कानून यूपीए (एन) और पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उन पर दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (एन) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन) के विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़की हिंसा में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए दावा किया कि दंगे भारत को अस्थिर करने और वैश्विक स्तर पर बदनाम

करने के उद्देश्य से रची गई एक सुनियोजित सत्ता परिवर्तन की साजिश का हिस्सा थे। पुलिस ने कहा कि उन्होंने गवाहों के बयान, दस्तावेज और तकनीकी सबूत जुटाए हैं जो आरोपियों को सांप्रदायिक आधार पर रची गई एक गहरी साजिश से जोड़ते हैं।

पुलिस ने याचिकाकर्ताओं पर तुच्छ आवेदनों और सुनियोजित असहयोग के माध्यम से जानबूझकर मुकदमे की कार्यवाही में देरी करने का भी आरोप लगाया। लगभग 900 गवाहों की मौजूदगी के कारण मुकदमे में वर्षों लगने के तर्क को खारिज करते हुए पुलिस ने इसे जमानत हासिल करने के लिए गढ़ा गया एक बहाना बताया और कहा कि केवल 100 से 150 गवाह ही महत्वपूर्ण हैं और यदि आरोपी सहयोग करें तो मुकदमा तेजी से आगे बढ़ सकता है।

चुनाव आयोग का कामकाज निष्पक्ष नहीं, भूपेश बघेल बोले-मतदाताओं के अधिकारों की हो रही लूट

रायपुर ०३/०१ (संवाददाता): छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) का कामकाज पक्षपातपूर्ण है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लाखों वोटों की गिनती का मुद्दा उठाया है। बघेल ने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों की लूट हो रही है। चुनाव आयोग का कामकाज निष्पक्ष नहीं है, और कई उदाहरणों से यह साबित हो चुका है। पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा है, और राहुल गांधी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया है। लाखों की संख्या में ये फर्जी वोट कहां से आ रहे हैं? ये सभी उदाहरण हैं जिनसे चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के बीच, समाजवादी पार्टी (एसपी) के सांसद राम गोपाल यादव ने बुधवार को



कहा कि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अज्यास में गड़बड़ी करने वाला असली दोषी जिला स्तर पर है। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोटों के हेरफेर के लिए असल में जिम्मेदार लोग प्रशासन का हिस्सा हैं और एक राजनीतिक दल की तरह काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ चुनाव आयोग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसे शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कलेक्टर और चुनाव आयोग एसआईआर करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन गड़बड़ी करने वाले असली दोषी जिला स्तर पर हैं। मैंने चुनाव आयोग से कहा था कि आप कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर लखनऊ में बैठे

लोग कलेक्टर को वोट काटने के लिए कहें, तो चाहे आप कितना भी कहें कि उनके वोट रहने चाहिए, वे कट जाएंगे। हम सिर्फ चुनाव आयोग को दोष नहीं दे सकते। प्रशासन से जुड़े वे लोग जो एक पार्टी की तरह काम कर रहे हैं, वे ही इन वोटों को इधर-उधर हेरफेर करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह तब सामने आया है जब संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के आठवें दिन लोकसभा में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू किए गए एसआईआर अज्यास पर चर्चा जारी है। वरिष्ठ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कल बहस की शुरुआत की, जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विपक्ष की ओर से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर चुनाव में धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया।

अमित शाह के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों का वाकआउट

नयी दिल्ली ०३/०१ (संवाददाता): संसद के निचले सदन (लोकसभा) में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी सुधारों पर चल रही चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन से वाकआउट कर दिया। वाकआउट के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर आरोप लगाए थे, तब विपक्ष ने वाकआउट नहीं किया था, लेकिन घुसपैठियों के मुद्दे पर वाकआउट कर दिया।

शाह ने कहा कि वे 200

बार बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन इस देश में एक भी घुसपैठिए को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। मैं घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात

कर रहा था। मैंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके (राहुल गांधी के) पिता और सोनिया जी पर कई आरोप लगाए थे।

कलिंग समाचार

THE KALINGA SAMACHAR

(A Hindi Daily News Paper)

PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH

FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT

AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16

ROURKELA, PH. 0661-2646999

PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)

E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

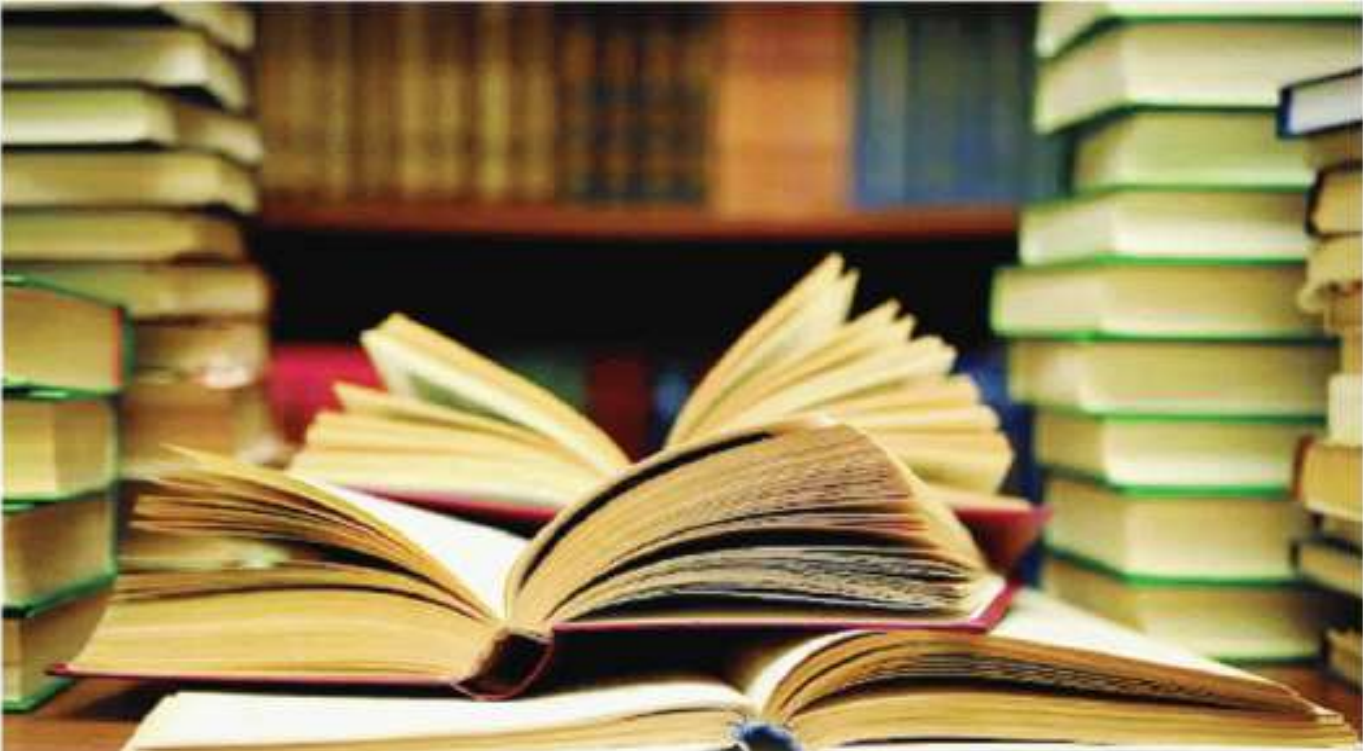


ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स को मिला 4.6 अरब साल पुराना उल्कापिंड

ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स की किस्मत उस समय खुल गई जब उसे यह पता चला कि जिस पत्थर को वह सोना समझकर रखे हुए है, वह दुर्लभ उल्कापिंड है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह उल्कापिंड सोने से भी ज्यादा कीमती है।

ऑस्ट्रेलिया में डेविड होल नामक शख्स ने सोना समझकर एक पत्थर को कई साल तक अपने घर में छिपाकर रखा। लाख प्रयास करने के बाद भी डेविड होल यह जान नहीं पाया कि आखिर इस पत्थर में सोना है या नहीं। डेविड बाद में उस पत्थर को लेकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न म्यूजियम पहुंचे। म्यूजियम वालों ने जब इस पत्थर को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई आम पत्थर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की यात्रा करके धरती पर पहुंचा उल्कापिंड था जो सोने से भी कीमती है। इसका वजन करीब 17 किलो है। डेविड को यह लाल और पीले रंग का भारी पत्थर साल 2015 में मेलबर्न के पास रोजनल पार्क में मिला था। 19वीं सदी में इस इलाके में कई सोने के पत्थर बख्तर आए थे और इसी वजह से लोगों को सोना मिलने की उम्मीद रहती है। डेविड को भी लगा कि उन्हें सोने का पत्थर मिला है। उन्होंने सोने को पाने के लिए पत्थर को तोड़ने के कई प्रयास किए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इससे यह पत्थर कई साल तक रहस्य बना रहा।

4.6 अरब साल पुराना
इसके बाद डेविड होल हाल ही में मेलबर्न के म्यूजियम में इस पत्थर को लेकर गए। इस पत्थर को देखने के बाद म्यूजियम के भूविज्ञानी डेनमार्क हेनरी ने सिडनी मॉनिंग हेराल्ड को बताया कि मैंने कई ऐसे पत्थर देखे थे जिसे लोगों ने उल्कापिंड बताया था। हालांकि मुझे केवल दो ही असली उल्कापिंड मिले हैं। उन्होंने कहा कि ताजा पत्थर गढ़े हुए हैं और गहरे हैं। यह तब होता है जब वे धरती के वातावरण में प्रवेश करते हैं। हेनरी ने उल्कापिंड के महत्व के बारे में कहा कि ये उल्कापिंड अंतरिक्ष में खोज का सबसे सस्ता तरीका मुहैया कराते हैं। वे हमें समय के अंदर ले जाते हैं और सोलर सिस्टम की उम्र, उसके निर्माण और रखरखाव के बारे में जानकारी देते हैं। कई उल्कापिंड तो हमारे ग्रह के गहरे आंतरिक हिस्से की झलक दिखाते हैं। कई उल्कापिंडों पर सितारों की धूल होती है जो हमारे सोलर सिस्टम से ज्यादा पुरानी होती है। उन्होंने अनुमान लगाया कि डेविड को मिला उल्कापिंड भंगल और वृक्षपाति ग्रह के बीच स्थित ऐस्टरॉइड बेल्ट से आया हो सकता है। यह उल्कापिंड 4.6 अरब साल पुराना हो सकता है। यह 100 से 1 हजार साल पहले धरती पर गिरा था।



ये है दुनिया की अनोखी किताबें

दुनिया में अनगिनत किताबें मौजूद हैं। इसमें धार्मिक से लेकर ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और अन्य विषयों की पुस्तक है, जिनसे मनुष्य सीखता समझता आया है। लेकिन इनमें से कुछ किताबें ऐसी हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही पुस्तकों की जानकारी देते हैं। दुनिया की इन अनोखी किताबों के बारे में जानकर आपको हैरानी जरूर होगी।



यह दुनिया की सबसे महंगी किताब है। आज के समय में अगर भारतीय रुपये में इसकी कीमत की बात करें तो वह 200 करोड़ से ज्यादा है। 15 वीं शताब्दी में इस किताब को लिखोनाडी द सिची ने लिखा था। 1994 में बिल गेट्स ने इसे 3.08 करोड़ डॉलर में खरीदा था।



बाइबिल
दुनिया में अगर अब तक सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं तो वह इसी किताब को पढ़ा गया है, तो वह ईसाई धर्म का ग्रंथ बाइबिल है। दुनिया भर में इस ग्रंथ की अलग-अलग भाषाओं में ढाई से लेकर 5 अरब प्रतियां मौजूद हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का रिकॉर्ड दिया है।

मिस मारपेल कलेक्शन



अगाथा क्रिस्टी की लिखी हुई मिस मारपेल दुनिया की सबसे मोटी किताब है। 8 किलोग्राम वजन किस किताब में 4032 पन्ने हैं।

शिकी नो कुसाबाना



प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है डेनमार्क का 'ब्लैक सन'

यद्यपि जब हजारों पक्षी एक साथ झुंड बनाकर आसमान में उड़ रहे हों? ये नज़ारा देखने के लिए डेनमार्क में लोगों की भीड़ पड़ती है क्योंकि हजारों पक्षियों का एक साथ उड़ना किसी 'कांते सुरज' जैसा प्रतीत होता है। जी हाँ, डेनमार्क का 'ब्लैक

किताबें मनुष्य के जीवन का सबसे अहम और जरूरी हिस्सा है जिसका इंसानी सभ्यता से सदियों पुराना नाता है। किताबों में वर्णित चीजों और ज्ञान से ही व्यक्ति को अपने इतिहास की जानकारी मिलती है और यही वर्षों से इंसानी सभ्यता के आगे बढ़ने की वजह रही है।

यह दुनिया की सबसे छोटी किताब है जो महज 22 पन्नों की है और इसका अकार 0.74 बाय 0.75 है। इसे जापानी भाषा में लिखा गया है और पढ़ने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करना होता है।

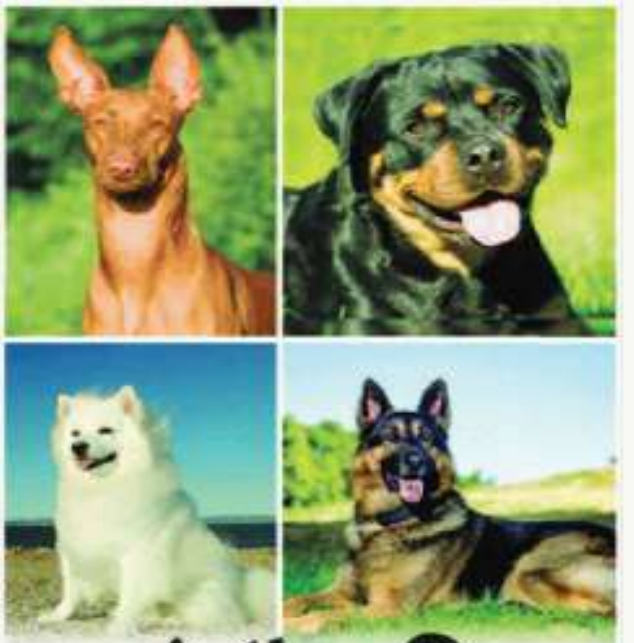
डायमंड सूत्रा



दुनिया की सबसे पहली और पुरानी प्रिंटेड किताब डायमंड सूत्रा है। बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच में संवाद की व्याख्या करने वाली इस पुस्तक को 868 वीं ईस्वी में जापान में छपाई तकनीकी विकसित होने के बाद छपा गया था।



सन' इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूरज ढलने के समय एक साथ हजारों पक्षी उड़ान भरते हुए नज़र आते हैं। ये आसमान में अलग-अलग के फॉर्मेशन बनाते हुए दिखते हैं। इसके साथ ही कई बार ये सूरज को पूरी तरह से ढक देते हैं। ये नज़ारे जुटलैंड में वैडन सी के बाद राइब आइलैंड में या टोंडर मार्शलैंड्स में देखने को मिलते हैं। मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है कि ये नज़ारा कितनी देर तक दिखेगा। वैसे आमतौर पर 20-30 मिनट ये अनोखा अनुभव लिया जा सकता है। मार्च से अप्रैल के बीच और सितंबर से अक्टूबर के बीच, दो बार यह अद्भुत दृश्य देख सकते हैं।



ये है दुनिया की सबसे महंगी डॉग ब्रीड्स

लोभों के बीच जब भी बफादारी की बात निकलती है तो हर किसी की जुबान पर सबसे पहले कुत्ते का नाम सामने आता है। अगर भी यद्यो ना क्योंकि इन्हें सदियों से सबसे बफादारी जानवर के रूप में पहचाना जाता है। इसका के इस सबसे करीबी दोस्त कि कई तरह की नस्लें दुनिया भर में मिलती है। लोग अपनी पसंद के अनुसार इन्हें अपने घर का सदस्य बनाना पसंद करते हैं। दुनिया में अलग अलग किस्म की कई डॉग ब्रीड हैं, जिन्हें बहुत पसंद किया जाता है। यह सब अपनी अलग-अलग खासियतों के चलते पहचाने जाते हैं। कोई अपने लंबे तो कोई छोटे कद के लिए प्रसिद्ध है। तो कोई ब्यूटनेस के चलते लोभों के बीच पहचाना जाता है। आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी ब्रीड बारे में बताते हैं जिन्हें खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करना होगी।

तिब्बतन मस्तिफ डॉग
तिब्बतन मस्तिफ तिब्बत में पाया जाने वाला एक डॉग है। इसके शरीर पर बाल काफी ज्यादा होते हैं और दूर से देखने पर यह बख्तर सेर की तरह नज़र आता है। इसकी कीमत की बात की जाए तो वह लगभग 11 करोड़ रुपये है।

फराओ हाउंड
ये डॉग्स देखने में काफी मासूम लगते हैं। इस ब्रीड में मेल डॉग की हाइट कीमेल डॉग से ज्यादा लंबी होती है। इनकी आंखें और कान सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी कीमत 5 लाख रुपये है।

रॉटविलर
यह दुनिया भर में डॉग की सबसे फेमस प्रजाति है और इसे पुलिस में भी शामिल किया जाता है। यह प्रजाति कई देशों की पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों को पकड़ने का काम

कर रही है। इसे खरीदने के लिए पाने दो लाख खर्च करने होंगे।

जर्मन शेफर्ड
सबसे महंगे डॉग की इस लिस्ट में जर्मन शेफर्ड नस्ल भी शामिल है। जो देखने में तो खतरनाक लगते हैं लेकिन यह काफी फंडली भी होते हैं।

अकिता
इस नस्ल के डॉग नॉर्थ जापान के पहाड़ी पर पाई जाने वाली बड़े डॉग्स की ब्रीड है। इनकी कीमत 32 हजार से शुरू होती है, जो 2 लाख तक जाती है।

चाउ चाउ
यह चीनी नस्ल का डॉग है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसका मुंह छोटा सा होता है, जो बालों के बीच छिप जाता है। इसे खरीदने के लिए आपको 2 लाख रुपये खर्च करने होंगे, जो इनकी शुरुआती कीमत है।

एरिकमो
ये कैनेडियन नस्ल का डॉग है। इनका मुंह बड़ा लम्बा होता है और ये बच्चों के साथ काफी फंडली होते हैं। इनकी कीमत 4 लाख से शुरू होती है।

सालुकी
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस ब्रीड को सबसे पुराना बताया जाता है। इन डॉग्स की हाइट काफी लंबी होती है और ये रिलम होते हैं। इनका चेहरा और कान भी लंबे होते हैं। इस डॉग की शुरुआती कीमत भी लाखों रुपये है।



इस दुनिया में आए हैं, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। चाय, बिस्कुट या हो कोई महंगी चीज आप हर चीज के लिए टैक्स देते हैं। अगर सैलरी अधिक है तो आपको तो देना ही देना है।

हम सब जानते हैं कि इनके लिए टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कुछ-कुछ टैक्स का मतलब समझ पाना मानो असंभव सा लगता है। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं, जहाँ सरकार बेफिजूल की चीजों पर टैक्स लगा कर लोभों से ऐसे ले रही है सरकारें, खास बात ये है कि इन टैक्स के नाम पढ़कर शायद आप मुस्कुराओ या कंप्यूज हो जाओ। चलिए इसी क्रम में दुनिया के कोने-कोने से अजीबो गरीब टैक्स की लिस्ट लेकर आए हैं जो अगर नहीं होते, टैक्स जैसी चीज मजेदार नहीं लगती, नज़र डालते हैं इन अजीबो गरीब टैक्स की लिस्ट पर

दुनिया के अजीबों गरीब टैक्स मुस्कुराओ या कंप्यूज हो जाओ

टैटू टैक्स
क्या आपने कभी सुना है की टैटू बनवाने के लिए भी टैक्स देना जरूरी होता है? लोग टैटू अपने शरीर पर कुछ यादों को छत्रवाने के लिए बनवाते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित अर्कॉसिस 2002 से विभिन्न टैटू स्टूडियो से सेल्स टैक्स लेता है।
बैचलर टैक्स
क्या मतलब कोई अपनी मर्जी से अकेले भी नहीं रह सकता है क्या? ये टैक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसौरी में लिया जाता है, यहाँ 21 साल से 50 साल के बैचलर पुरुषों से 1 डॉलर टैक्स लिया जाता है।

कट्टू टैक्स
कट्टू सुनते ही दिमाग में हेलोवीन का त्योहार आ जाता है, जहाँ लोग खूब सज्जते और संपरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यू जर्सी (संयुक्त राज्य अमेरिका) में कट्टू एक कर-मुक्त खाना है, लेकिन अगर इसे पेट, वर्निश या काटकर और सजावट के रूप में बेचा जाता है, तो इसपर सेल्स टैक्स लगता है।
खिड़की टैक्स
इस टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा जाता है, इस टैक्स को लगाने का एक ही उद्देश्य था, इस टैक्स में लोगों के घरों में कितनी खिड़कियां हैं, उसपर लगता था, ताकि अमीर और गरीब का पता लगाया जा सके, लेकिन बाद में इन देशों द्वारा इस तरह के

करधन के खिलाफ बहुत से आंदोलन के कारण इसे खत्म कर दिया गया था।
ब्लूबेरी टैक्स
ब्लूबेरी टैक्स फलों की अधिक कटाई को रोकने के लिए लगाया जाता है, जो बदले में वनस्पति को पानपान में मदद करता है, यूनाइटेड स्टेट्स के मेन में काफी ज्यादा है, इसीलिए मेन में, ब्लूबेरी के उत्पादन पर प्रति बाउंड डेड पैसा टैक्स लगाया जाता है, प्लेइंग कार्ड टैक्स
एक कारण है कि अलबामा अपने कैसीनो के लिए क्यों नहीं जाना जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण टैक्स है, अलबामा संघ का एकमात्र राज्य है जिसने राज्य के भीतर खरीदे गए कार्डों के डेक के लिए 10% प्लेइंग कार्ड टैक्स चार्ज करता है,

टॉयलेट पलश टैक्स
पानी के खर्च पर नज़र रखने के लिए ये टैक्स मेरीलैंड में लगाया था, जहाँ 5 डॉलर प्रति माह का टैक्स लगाया है, जो बाद में मेरीलैंड सीक्रेज ट्रीटमेंट सिस्टम में जाता है।
कैडी टैक्स
कोई टॉफी और कैडी पर कैसे टैक्स लगा सकता है? लेकिन Chicago में ऐसा होता है, कैडी अगर मैदा या आटा से बनी हो, तो उसपर साधारण टैक्स लगता है, वहीं अगर कैडी बिना मैदा के बनती है, तो उसपर 5.25% का टैक्स लगाया जाता है।
फैट टैक्स
भारत के केरल राज्य में 14.5% का टैक्स लिया जाता है, ताकि लोग काम मात्रा में जंक खाना खाए और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें।
एंटरटेनमेंट टैक्स
फैट टैक्स ही नहीं, बल्कि भारत में एंटरटेनमेंट टैक्स भी लिखा जाता है, हाँ, एक स्पेशल तरह का टैक्स है, जो स्पोर्ट्स ड्रैफ्ट, मूवीज और थिएटर शो पर लगता है जो हर एक राज्य में अलग-अलग होता है,

कलिंग समाचार



संपादकीय

रविवार 04 जनवरी 2026

अरावली को मृत्युदंड

पर्यावरण संरक्षण का मोदी सरकार का वादा उसके बाकी वादों की तरह न केवल खोखला है, बल्कि डरावना भी है। इस संरक्षण के नाम पर सरकार ने एक उद्योगपति को निजी जंगल बनाकर उसमें तमाम तरह के जानवर पालने की अनुमति दे दी। पूरी दुनिया में ऐसे भ्रष्टाचार की मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन पर्यावरण को लेकर सरकार के खौफनाक रवैये का यह अकेला उदाहरण नहीं है। नया उदाहरण 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला को सुप्रीम कोर्ट के जरिए मृत्युदंड सुनाने का है। सरकार की बनाई कमेटी की तय परिभाषा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन की जो अनुमति दी है, वह किसी मृत्युदंड से कम नहीं है। अगड़े-पिछड़े, लोकतांत्रिक-तानाशाही वाले तमाम देशों में पर्यावरण के मुद्दों पर व्यापक बहस होती है, फिर भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन भारत शायद इकलौता देश है जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर केंद्र की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी और इसमें पर्यावरणविदों की राय जरूरी नहीं समझी गई। सरकार ने किसी पर्यावरणविद को भले सलाहकार नहीं बनाया, फिर भी अरावली में खनन के खिलाफ जो आवाजें चारों तरफ से उठ रही हैं, उन पर ही सर्वोच्च न्यायाल को स्वतन्त्र संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या गलत हो रहा है, जिस पर इतना विरोध हो रहा है। गौरतलब है कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्यों के वन विभागों और सेंट्रल ए पावर्ड कमेटी के सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसे अरावली को परिभाषित करने को कहा गया। कमेटी ने कोर्ट के सामने अपनी अनुशंसा में कहा कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात इन चार राज्यों में लगभग 670 किमी तक फैली अरावली पहाड़ियों में वही पहाड़ियां अरावली श्रृंखला का हिस्सा मानी जायें जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, पूरी अरावली श्रृंखला में 12,081 पहाड़ियां हैं जिनमें से मात्र 1048 पहाड़ियां ही यानी केवल 8.7 प्रतिशत हिस्सा ही सरकार के 100 मीटर के मानक पर खरी उतरता है। जिस पहाड़ी की ऊंचाई 99 मीटर है, उसे भी सरकार ने पहाड़ी नहीं माना है। कमेटी की अनुशंसाओं से असहमति जताते हुए न्यायमित्र वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने अरावली श्रृंखला की नई परिभाषा का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने इससे पहले अरावली की परिभाषा को लेकर जो नियम बनाये थे, उसके अनुसार, 3 डिग्री से अधिक ढाल, जिसमें घाटियों की चौड़ाई 500 मीटर हो, उसे अरावली श्रृंखला का हिस्सा समझा जाये, इसके अतिरिक्त पहाड़ी के नीचे (तलछटी) में 100 मीटर की चौड़ाई तक किसी भी किस्म की कोई गतिविधि ना की जाये। लेकिन अब तो नया खेल करके सौ मीटर ऊंचाई का मापदंड बना दिया गया है। जिसके बाद इन पहाड़ियों के मनचाहे खनन का खेल खेलने के लिए मैदान साफ है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 4 दिसंबर को द हिंदू में प्रकाशित अपने लेख में इसे अरावली के लिए एक डेथ वारंट यानी मृत्युदंड का ऐलान बताया था। उन्होंने लिखा था कि यह निर्णय उन समूहों के लिए वरदान है जो अवैध खनन और जमीन कब्जे में शामिल रहते हैं। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि अरावली सदियों से उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखने, थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने और राजस्थान के जंगलों को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब रोज़मर्रा की समस्या नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े जन-स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। देश के दस बड़े शहरों में सालाना 30 हजार से अधिक मौतें सिर्फ प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन संरक्षण नियम 2022 में संशोधन कर प्राकृतिक संसाधनों के गलत तरीके से दोहन का रास्ता खोला है, ताकि कुछ उद्योगपतियों के मुनाफे की हवस पूरी हो सके। इसके बदले भाजपा को करोड़ों का चंदा मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी सत्ता बनाए रखने और मनमाने फैसले लेने में करती है।

बाबा मायाराम

देशी धान की खासियत होती है, वह स्वाद में बेजोड़ होती हैं। इसलिए दाम भी अच्छा मिलता है जबकि हाईब्रीड में स्वाद नहीं होता। देशी धान में गोबर खाद डालने से धान की पैदावार हो जाती है। जबकि हाइब्रीड या बौनी किस्मों में रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। जिससे तागत बढ़ती है और भूमि की उर्वरक शक्ति भी कम होती है।

हाल ही मेरी बाबूलाल दाहिया से बात हुई। वे सतना जिले के पिथौराबाद गांव में रहते हैं। वे देशी बीजों के संरक्षण में लगे हैं और इसके लिए उन्हें पंचश्री स मान से भी नवाजा गया है। आज के इस कॉलम में उनके अनूठे काम पर चर्चा करना चाहूंगा।

बाबूलाल दाहिया मूलतः बघेली के कवि रहे हैं। लेकिन कई सालों से देशी बीजों को बचाने में जुटे हैं। मैं उनके गांव तीन-चार बार गया हूं और उनके साथ ल बी यात्राएं भी की हैं। गांव में वे खेती में देशी बीज बोते हैं, और उनका संग्रह करते हैं। उन्होंने देशी बीज बैंक भी बनाया है, जहां से किसानों को बीज भी देते हैं। हालांकि वे पिछले कुछ समय से एक अनूठे संग्रहालय को बनाने में लगे हैं, जिसमें उन्होंने खेती किसानी से लेकर ग्रामीण जनजीवन में काम आने वाली चीजों को संजोया है।बाबूलाल दाहिया की कुल 8 एकड़ जमीन है जिसमें से 2 एकड़ में ही देशी धान का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी 6 एकड़ में भी देशी किस्में लगाते हैं, वह भी बिना किसी रासायनिक खाद के। साथ ही उचहेरा ब्लाक के 30 गांवों में भी किसानों के साथ मिलकर धान और पौष्टिक अनाज (कोदो,कुटकी,ज्वार) की खेती कर रहे हैं।

बाबूलाल दाहिया की खेती-किसानी के साथ-साथ साहित्य में रूचि रही है। वे बघेली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। लेकिन जब से उन्हें यह हहसास हुआ कि जैसे लोकगीत व लोक संस्कृति लुप्त हो रही है, तबसे उन्होंने देशी धान की लुप्त हो रही है, तबसे उन्होंने इन्हें सहेजने और बचाने का काम शुरू कर दिया।उनके पास देशी धान की 100 से ज्यादा किस्में हैं। इन सभी धान के गुणधर्मों का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है।वे हर साल इन्हें अपने खेत में बोते हैं और अध्ययन करते हैं। दाहिया जी कहते हैं हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि धान और कोदो हमारे अपने क्षेत्र के अन्न हैं। इन दोनों के जंगली स्वरूप अब भी मौजूद हैं। धान की जंगली किस्म को पसही कहते हैं। हलशष्टी त्योहार की महिलाएं व्रत करने के बाद इसका ही चावल खाती हैं। पसही धान डबरों, पोखरों में होता है। यह ऐसी ही हर साल पोखरों और डबरों में हर साल अपने आप उगती है, झड़ती है और वंश परिवर्तन (बीजों में बदलाव) करती जाती है। मनुष्य ने इनके गुणधर्मों का अध्ययन कर कालांतर में जंगली डबरों से अपने द्वारा बनाएं पानी वाले खेतों में इसे उगाना शुरू किया होगा, जहां लंबे समय तक पानी संचित रहे। बाद में चावल हमारे भोजन में शामिल हो गया।

वे बताते हैं कि पहले हमारे क्षेत्र में पचासों तरह की धानें हुआ करती थी। इनमें बहुत विविधता है। जैसे गलरी पक्षी की आंख की तरह होता है गलरी धान। इसी तरह किसी धान का दाना सफेद होता है तो किसी का लाल। किसी का काला तो किसी का बैंगनी, किसी का मटमैला। कुछ का दाना पतला तो किसी का मोटा और कोई गोल तो किसी का दाना लंबा। कुछ धान की किस्मों के पौधे हरे होते हैं तो किसी के बैंगनी। इनमें न केवल विविधता है बल्कि अलग-अलग रूप रंग का अपना विशिष्ट स्वाद व अपूर्व सौंदर्य है। परंपरागत देशी धान की विविधता के कई किस्से-कहानियां जनश्रुतियों में मौजूद हैं।

अरविन्द मोहन

नितिन नबीन कुछ ज्यादा ही नये लगते हैं। पूरे देश की कौन कहे(वैसे भाजपा अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है) पूरे बिहार के लोग भी उनको नहीं जानते होंगे। यही भाजपा उनको बिहार का अध्यक्ष बनाने का साहस नहीं दिखा सकती थी। वे बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, उनके पिता का भी भाजपा से जुड़ाव था। उनकी असमय मौत से उपजी सहानुभूति के चलते ही उनकी कायस्थ प्रभाव वाली सीट पर हुए उप चुनाव में नितिन नबीन को टिकट मिला।

नितिन नबीन का भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना भारतीय राजनीति की एक

परिघटना है। इस चलते भी उस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा हो रही है और यह जरूरी भी है। वे चौथी बार विधायक बने थे, मंत्री भी हैं और एकदम युवा हैं।

चाचा और भैया स बोधन उनका प्रिय जुमला है और एक चाचा नीतीश कुमार द्वारा उनको सदन में तुम कहकर हड़काए जाने का प्रसंग काफी लोगों को याद आ रहा है। नितिन का चुनाव एक कार्यकर्ता को महत्व देने का प्रमाण है और इसके चलते भाजपा को अलग चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी बताना भी जारी है। यह चीज भाजपा के लिए खास है क्योंकि कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, तेलगु देशम, अकाली, शिव

देशी बीज

हो रही है, वैसे ही लोक अन्न भी लुप्त हो रहे हैं, तबसे उन्होंने

इन्हें सहेजने और बचाने का काम शुरू कर दिया।उनके पास देशी धान की 100 से ज्यादा किस्में हैं। इन सभी धान के गुणधर्मों का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है।वे हर साल इन्हें अपने खेत में बोते हैं और अध्ययन करते हैं। दाहिया जी कहते हैं हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि धान और कोदो हमारे अपने क्षेत्र के अन्न हैं। इन दोनों के जंगली स्वरूप अब भी मौजूद हैं। धान की जंगली किस्म को पसही कहते हैं। हलशष्टी त्योहार की महिलाएं व्रत करने के बाद इसका ही चावल खाती हैं। पसही धान डबरों, पोखरों में होता है। यह ऐसी ही हर साल पोखरों और डबरों में हर साल अपने आप उगती है, झड़ती है और वंश परिवर्तन (बीजों में बदलाव) करती जाती है। मनुष्य ने इनके गुणधर्मों का अध्ययन कर कालांतर में जंगली डबरों से अपने द्वारा बनाएं पानी वाले खेतों में इसे उगाना शुरू किया होगा, जहां लंबे समय तक पानी संचित रहे। बाद में चावल हमारे भोजन में शामिल हो गया।

वे बताते हैं कि पहले हमारे क्षेत्र में पचासों तरह की धानें हुआ करती थी। इनमें बहुत विविधता है। जैसे गलरी पक्षी की आंख की तरह होता है गलरी धान। इसी तरह किसी धान का दाना सफेद होता है तो किसी का लाल। किसी का काला तो किसी का बैंगनी, किसी का मटमैला। कुछ का दाना पतला तो किसी का मोटा और कोई गोल तो किसी का दाना लंबा। कुछ धान की किस्मों के पौधे हरे होते हैं तो किसी के बैंगनी। इनमें न केवल विविधता है बल्कि अलग-अलग रूप रंग का अपना विशिष्ट स्वाद व अपूर्व सौंदर्य है। परंपरागत देशी धान की विविधता के कई किस्से-कहानियां जनश्रुतियों में मौजूद हैं।

भाजपा अध्यक्ष बनाने की

सेना समेत ज्यादातर पार्टियों में नेतृत्व एक परिवार तक सिमट आया है। फिर यह भी हुआ है कि पार्टियां निरंतर एक काकस के घेरे में दिखती हैं- भाजपा

बार-बार इस घेरे को तोड़कर नये लोगों को मौका देती है और इनमें योगी आदित्यनाथ जैसे लोग धाकड़ नेता बनकर उभरते हैं तो शिवराज सिंह जैसा धाकड़ भी अनुशासित सिपाही बनकर पार्टी की सेवा करता रहता है। जो नाराज और मुंह फुलाए हैं वे पार्टी का खास नुकसान नहीं कर पाते या उसकी हि मत नहीं करते।

बहुत पहले जब भाजपा नई थी और बारी- बारी से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाकर अपना काम आगे बढ़ा रही थी तब किसी बात पर आडवाणी जी और समाजवादी नेता मधु लिमए में बहस छिड़ी। फिर मधु जी ने चुनौती दी कि भाजपा किसी तीसरे को अध्यक्ष बनाकर दिखाए।

उनका इशारा भाजपा में बड़े नेताओं की कमी से भी ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंजूरी की तरफ था। आज मधु लिमए होते तो उनको न सिर्फ अपने शब्द वापस लेने पड़ते बल्कि अपने शिष्यों द्वारा एक आंदोलन को छोटे-छोटे दल बनाकर पारिवारिक जागीर

राउरकेला, रविवार 04 जनवरी 2026

देशी बीज बचाने वाले बाबूलाल दाहिया

हैं। उनके देशी धान का बड़ा संग्रह है। इनमें से कुछ धान सुगंधित हैं तो कुछ बिना सुगंध की। कम अवधि में पकने वाली किस्मों से लेकर लंबी अवधि की किस्में हैं। हल्की और कम भराव वाली जमीन में 70 से 75 दिन में पकने वाली सरया, सिकिया, श्यामजीर, डिहुला, सरेखनी किस्में हैं तो मध्यम समय में 100 से 120 दिन में पकने वाली नेवारी, झोलार, करगी,

देशी धान को बार-बार निंदाई की

जरूरत नहीं पड़ती। एक बार निंदाई हो

जाए तो बहुत है। क्योंकि इसके पौधे को

खरपतवार नहीं दबा पाती। क्योंकि इसका

पौधा काफी ऊंचा होता है। कीट व्याधि

को मकड़ी, मधुमक्खी, चींटी और मित्र

कीट ही नियंत्रित कर लेते हैं। केंचुएं

निस्वार्थ भाव से 24 घंटे गुड़ाई कर जमीन

को भुरभुरा बनाते हैं, खेत को बखरते हैं

जिससे पौधे की बढ़वार में मदद मिलती

है। वे बताते हैं कि हमारे पूर्वज बादलों

के रंग, हवा के रुख, अवर्षा, खंड वर्षा

का पूर्वानुमान लगाने में माहिर थे।

मुनगर, सेंकुरगार आदि हैं।

इसके अलावा 120 से 130 दिनों में पकने वाली बादल फूल, केराख ह, बिष्णुभोग, दिलबक्सा आदि धान किस्में शामिल हैं। लैला-मंजजू धान में दो सफेद दाने निकलते हैं। कलावती का पत्ता भी काला होता है। गांजाकली अधिक उत्पादन देती है। अलग-अलग किस्मों को बोने के कारण हैं। किसान ऐसी धान खेत में बोता है, जो खेत मांगता है। यानी हल्की जमीन वाला खेत है तो जल्दी पकने वाली धान बोएगा। कुछ धान की किस्में ऐसी होती हैं जिन्हें किसान अपने खाने के लिए बोते हैं। बजरंगा ऐसा ही धान है, जो जल्द हजम

जुड़ी एक कहावत भी है-

धान बोवै करगी, सुवर खाय न समधी। यानी किसान को करगी धान बोना चाहिए क्योंकि बाल में सकुर कांटे होने के कारण समधी को भी नहीं खिलाई जाती देशी धान की खासियत बताते हुए वे कहते हैं कि वह स्वाद में बेजोड़ होती हैं। इसलिए दाम भी अच्छा मिलता है। जबकि हाईब्रीड में स्वाद नहीं होता। देशी धान में गोबर खाद डालने से धान की पैदावार हो जाती है। जबकि हाइब्रीड या बौनी किस्मों में रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। जिससे लागत बढ़ती है और भूमि की उर्वरक शक्ति भी कम होती है। देशी धान ऋतु के प्रभाव

से पक जाती है। जैसे कोई एक ही किस्म की धान अलग-अलग समय में बोई जाए तो वे एक ही समय पक कर तैयार हो जाती हैं। यानी एक ही किस्म को अगर हम 1 जुलाई को बोएं और उसी किस्म को 1 अगस्त को बोएं तो वे एक साथ या कुछ दिनों के अंतर से ही पककर तैयार हो जाएंगी।

देशी धान को बार-बार निंदाई की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार निंदाई हो जाए तो बहुत है। क्योंकि इसके पौधे को खरपतवार नहीं दबा पाती। क्योंकि इसका पौधा काफी ऊंचा होता है। कीट व्याधि को मकड़ी, मधुमक्खी, चींटी और मित्र कीट ही नियंत्रित कर लेते हैं।केंचुएं निस्वार्थ भाव से 24 घंटे गुड़ाई कर जमीन को भुरभुरा बनाते हैं, खेत को बखरते हैं जिससे पौधे की बढ़वार में मदद मिलती है। वे बताते हैं कि हमारे पूर्वज बादलों के रंग, हवा के रुख, अवर्षा, खंड वर्षा का पूर्वानुमान लगाने में माहिर थे। जैसे एक कहावत है कि पुरबा जो पुरबाई पावै, सूखी नदियां नाव चलावैं। यानी पूर्वा नक्षत्र में पुरवैया हवा चलने लगे तो इतनी वर्षा होती है कि सूखी नदियों में इतना पानी हो जाता है कि नाव चलती लगे।

वे आगे बताते हैं कि जैसे हमारे देशी बीज खत्म हो रहे हैं वैसे ही उससे जुड़े व परंपरागत खेती से जुड़े कई शब्द भी खत्म हो रहे हैं। पूरी कृषि संस्कृ ति और जीवन पद्धति खत्म हो रही है। अब हमारा काम गेहूं, चावल और दाल जैसे शब्द से चल जाता है। लेकिन पहले बहुत सारे अनाज होते थे। उनके नाम थे जैसे समा, कोदो, कुटकी, मूंग, उड़द, ज्वार, तिल्ली आदि। फिर उन्हें बोने से लेकर काटने तक कई काम करने पड़ते थे। बोंवनी, बखरनी, निंदाई-गुड़ाई, दाबन, उड़ावनी और बीज भंडारण आदि। खेती की हर प्रक्रिया के अलग-अलग नाम

पर भारी पड़े होंगे। बिहार में कायस्थ इस बार काफी नाराज थे जो लगभग शत प्रतिशत भाजपा को वोट देते आये थे। पिछली विधान सभा में तीन विधायक कायस्थ थे जबकि इस बार सिर्फ एक को टिकट मिला। बिहार से ज्यादा बड़ा कारण पश्चिम बंगाल का आगामी विधान सभा चुनाव है जहां कायस्थ ज्यादा बड़ी और प्रभावी जाति है। बंगाल चुनाव में भाजपा हिन्दू-मुसलमान साथ हों, उनका धुवीकरण हो, नामशूद्र भाजपा के ठोस समर्थक हों, इन तीनों रणनीति पर काम करके भाजपा सफल नहीं हुई है।

इस बार भी पंचायत चुनाव में काफी मुसलमान उ मीदवार देकर भी उसे सफलता नहीं मिली है। इसकी वजह बंगाली समाज में जाति और संप्रदाय की पूछ कम होने और भद्रलोक में भाजपा की पैठ न होना है। मु यतः ब्राह्मण, कायस्थ और बैद्य जातियों वाले भद्रलोक में कायस्थों के मन में मुलायमियत लाकर यह चुसपैठ की जा सकती है, यह बात भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। और अगर भाजपा बंगाल का किला भेदने में इस रणनीति में सफल होती है तो वह बार-बार ऐसा अध्यक्ष लाना चाहेगी। वह क्या कोई भी जीवंत और महत्वाकांक्षी पार्टी ऐसा फैसला करेगी।

थे। यह जरूर है कि ये शब्द किसी शब्दकोष में नहीं लेकिन लोक मानस में थे। बुजुर्ग अब भी इन शब्दों को आत्मीय ढंग से याद करते हैं। लेकिन खेती का फसलचक्र बदलने से, एकल खेती होने से ये शब्द भी लोप हो रहे हैं।

बौनी किस्मों और देशी धान का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले दाहिया ने बताया कि देशी किस्मों में स्थानीय हवा-पानी के अनुकूल अपने आपको ढालने की क्षमता होती है। जैसे निरंतर सूखे से लड़ते और हजारों सालों से इस भूमि में उगते-उगते देशी धान ने अपना ठंडल बड़ा कर लिया था जिससे वह अपने पौधे में अधिक पानी का संचय कर सके। बाद में बाल आ जाने के पश्चात वे ओस में ही पक जाती हैं। बाहर से आयातित बौनी किस्मों में वह गुण नहीं है। वे कहते हैं कि यहां की नदियों में पानी उत्तर भारत की तरह हिमनदी नहीं हैं, जहां साल भर पानी रहता है। वहां वर्षा हो या न हो, बर्फ पिघलने के कारण नदियों में पानी बना रहता है। हमारे यहां की नदियां हिम पुत्री नहीं है, वन पुत्री हैं। लेकिन इन नदियों में पानी तभी होगा जब वन होंगे पर वन जब होंगे तब हम पानी की किफायत बरतेंगे। अगर हम तीन-तीन, चार-चार पानी वाली फसलें लगाएंगे तो धरती शुष्क होगी। पेड़-पौधे सूख जाएंगे। जब वन नहीं होंगे तो बारिश नहीं आएगी जैसे बिना हवाई अड्डा के हवाई जहाज नहीं उतरता वैसी ही बिना वन के बादल भी नहीं उतरते। यानी बारिश भी नहीं होती। इसीलिए धान की खेती को लंबे समय तक करना है तो वनों को बचाना जरूरी है और कम पानी वाली देशी किस्मों की खेती करना जरूरी है। कुल मिलाकर, बाबूलाल दाहिया के काम से देशी अनाज और गांव-समाज की संस्कृति के संरक्षण में अमूल्य योगदान दिया है और लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या हम भी कुछ उनसे सीखना चाहेंगे?

पर भारी पड़े होंगे। बिहार में कायस्थ इस बार काफी नाराज थे जो लगभग शत प्रतिशत भाजपा को वोट देते आये थे। पिछली विधान सभा में तीन विधायक कायस्थ थे जबकि इस बार सिर्फ एक को टिकट मिला। बिहार से ज्यादा बड़ा कारण पश्चिम बंगाल का आगामी विधान सभा चुनाव है जहां कायस्थ ज्यादा बड़ी और प्रभावी जाति है। बंगाल चुनाव में भाजपा हिन्दू-मुसलमान साथ हों, उनका धुवीकरण हो, नामशूद्र भाजपा के ठोस समर्थक हों, इन तीनों रणनीति पर काम करके भाजपा सफल नहीं हुई है। इस बार भी पंचायत चुनाव में काफी मुसलमान उ मीदवार देकर भी उसे सफलता नहीं मिली है। इसकी वजह बंगाली समाज में जाति और संप्रदाय की पूछ कम होने और भद्रलोक में भाजपा की पैठ न होना है। मु यतः ब्राह्मण, कायस्थ और बैद्य जातियों वाले भद्रलोक में कायस्थों के मन में मुलायमियत लाकर यह चुसपैठ की जा सकती है, यह बात भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। और अगर भाजपा बंगाल का किला भेदने में इस रणनीति में सफल होती है तो वह बार-बार ऐसा अध्यक्ष लाना चाहेगी। वह क्या कोई भी जीवंत और महत्वाकांक्षी पार्टी ऐसा फैसला करेगी।

^[1] बाबूलाल दाहिया मूलतः बघेली के कवि रहे हैं



झारखंड लोक सेवा आयोग ने 151 अभ्यर्थियों तेज रफ़्तार ट्रैक्टर ने बाइक को दिया झटका, रद्द किए गए आवेदन

सवार को कुचला एक की मौत

रांची ०३/०१ (संवाददाता): झारखंड लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा पदाधिकारी के बैकलाग पदों पर होनेवाली नियुक्ति में 151 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए हैं। आयोग ने इन अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। साथ ही आयोग ने कुल 26 पदों के विरुद्ध 30 अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्रों की जांच के लिए बुलाया है। इनके प्रमाणपत्रों की जांच 24 मार्च को आयोग कार्यालय में होगी। बताते चलें कि इन पदों के लिए आयोग ने वर्ष 2023 में ही आवेदन मंगाए थे लेकिन



अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रमाणपत्रों की जांच के लिए तिथि निर्धारित की है। प्रमाणपत्रों की जांच के बाद साक्षात्कार की तिथि की घोषणा की

जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के बाद नियुक्ति प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। आयोग ने चिकित्सा पदाधिकारी की बैकलाग नियुक्ति प्रक्रिया के तहत प्रमाणपत्रों की जांच की तिथि तय कर दी है। आवश्यक अर्हता रखनेवाले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच 24 मार्च को आयोग कार्यालय में सुबह

दस बजे से शाम पांच बजे तक होगी। आयोग ने मंगलवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी। प्रमाणपत्रों की जांच के बाद साक्षात्कार की तिथि की घोषणा की जाएगी। आयोग ने बैकलाग नियुक्ति के तहत चिकित्सा पदाधिकारी के 26 पदों पर नियुक्ति के लिए जून-जुलाई 2023 में ही आवेदन आमंत्रित किए थे लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। कुल 26 पदों में 25 पद अनुसूचित जनजाति तथा एक पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बताते चलें कि लंबे समय तक पद रिक्त रहने के बाद हाल ही में पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते की नियुक्ति अध्यक्ष के पद पर हुई है। अध्यक्ष के पद रिक्त रहने के कारण सभी नियुक्ति प्रक्रिया

लंबित थी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मंगलवार को प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपित राम नारायण सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 27 फरवरी को याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में आरोपित रांची के एडीएम विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक की याचिका भी पूर्व में खारिज हो चुकी है। मामले में अब तक अदालत ने 30 आरोपितों को अग्रिम राहत देने से इन्कार किया है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 अप्सरों सहित 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।



गिरि डीह ०३/०१ (संवाददाता): बरसीडीह रोड जेपी हॉस्पिटल के समक्ष सोमवार को ट्रैक्टर और बाइक में सीधी टक्कर हुई। जिससे बाइक सवार कुरैशी मोहल्ला निवासी शकील कुरैशी का 17 वर्षीय पुत्र अरमान कुरैशी की मौत घटना स्थल पर हो गई। जबकि 26 वर्षीय बाइक सवार हुट्टी बजार निवासी मो आप्ताब

कुरैशी उर्फ सुगना कुरैशी गंभीर रूप से जख्मी हो गया स्थानीय लोगों सुगना कुरैशी की स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने घायल युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया गया है। सड़क दुर्घटना में अरमान कुरैशी की मौत एवं आप्ताब कुरैशी गंभीर रूप से

घायल होने की सूचना पाकर मृतक के परिजन के साथ 100 से अधिक लोग सदर अस्पताल पहुंचे और चीत्कार के बीच भारी हंगामा करने लगे। सदर अस्पताल में हंगामा होने की सूचना पाकर नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी दर्जनों पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने वालों को खदेड़ कर बाहर निकाला।



आज का राशिफल

मेघ – आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ विशेष रहेंगी। मन में द्विधा रहने से ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार न करने की गणेशजी की सलाह है। वृषभ – गणेशजी कहते हैं कि व्यापार में वृद्धि होने के साथ व्यापार के सञ्बंध में सौदे लाभदायक साबित होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। बुजुर्गों तथा मित्र मंडल से लाभ और सुखद क्षणों का अनुभव मिलेगा। मिथुन – शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। नौकरी – व्यवसाय में आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्क – गणेशजी कहते हैं कि आज आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। तथा विदेश से अच्छे समाचार आएँगे। सिंह – आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। निषेधात्मक विचार आपको गलत मार्ग पर न ले जाए, उसका ध्यान रखने के लिए गणेशजी कहते हैं। कन्या – गणेशजी की कृपा से दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ज्वाति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। मनोरंजन की प्रवृत्तियों में भाग लेंगे। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी। तुला – गणेशजी कहते हैं कि सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति के भी तबीयत में सुधार होगा। घर में सुख- शांति के वातावरण में आप समय व्यतीत करेंगे। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। वृश्चिक – आज यात्रा प्रवास का आयोजन न करने की सलाह गणेशजी देते हैं। स्वास्थ्य के सञ्बंध में चिंतित रहेंगे। संतानों के सञ्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। धनु – गणेशजी कहते हैं कि आज आपको अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव खड़े होने की संभावना है। मन में उठनेवाली द्विधाओं से आप मानसिक उचाट अनुभव करेंगे। मकर – आज आप रणनीति में शत्रुओं को परास्त करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। आप हरेक कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। व्यापार- धंधे में लाभ होगा। कुंभ – गणेशजी बताते हैं कि मन में द्विधाएँ खड़ी होने से आप कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुँच सकेंगे। महज्ज्वपूर्ण निर्णय न लें। वाणी पर संयम नहीं रहनेसे पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है। मीन – आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। नए कार्य हाथ में लेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। धार्मिक मांगलिक प्रसंगों में जाएँगे।

रांची ०३/०१ (संवाददाता): विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 74 अरब 70 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपये की अनुदान मांग चर्चा के बाद स्वीकृत हो गई। विभागीय मंत्री डॉ. इरफन अंसारी ने सरकार के उजर में विपक्ष पर जहाँ चुटकियाँ लीए वहीं आगामी योजनाओं को भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सदर अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी तकनीक को अपनाया जाएगा। इसकी शुरुआत रिज्स से होगी। सभी सरकारी अस्पतालों में 10 रुपये में 10 तरह की जांच होगी। इनमें सिकल सेल अनीमियाए डेंगूए मलेरियाए फाइलेरियाए सीबीसीए क्रेटिनीनए ज़लड शुगरए चिकुनगुनियाए रूटीन यूरीन व



कोविड.19 की जांच शामिल हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे 6500 करोड़ की लागत से रिज्स का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। इससे रिज्स की क्षमता को 2200 बेड से बढ़ाकर 3500 बेड करने जा रहे हैं। सुपर स्पेशियलिटी की क्षमता 200 से बढ़ाकर 950 बेड की करेंगे। इसके लिए 750 बेड का नया सुपर स्पेशियलिटी भवन बनेगा। 5000 क्षमता का नया ओपीडी भवन बनेगा। इसमें ओपीडी के अलावा सभी प्रकार की जांच एक ही भवन में होंगे। यूजीए पीजी छात्र-छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनेंगे। सभी हॉस्टल तोड़कर ज़लैट कल्चर विकसित होगा। 14 मंजिला छात्रावास बनेगा। यहां दूसरा रिज्स भी बनने जा रहा है जिसके लिए जमीन चिह्नित कर लिया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में घोषणा की है कि सदर अस्पताल में 24 गुणा सात सुपर स्पेशियलिटी सेवा देंगे। मेडिकल कॉलेजों के लिए एमआरआई सीटी स्कैन मशीनए डिजिटल एक्सरे खरीद रहे हैं इसके लिए आपूर्तिकर्ता

से एक शर्त भी रखी जा रही है कि उक्त मशीनें उन्हें ही संचालित करनी है। इसके लिए उनसे दस साल का अनुबंध लिया जाएगा। सभी सदर अस्पताल में आईसीयू और जिला अस्पतालों में माइयूएल ओटी बनाने जा रहे हैं राज्य के गांवों में 25 हेल्थ कैंटेज बनाएंगे। ये सिर्फ ट्राइबल क्षेत्र में बनेंगे ताकि वहां के ग्रामीणों को गांव में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। दो वर्ष के भीतर राज्य में 1258 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण

होगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में संचालित पांचों चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी की सेवाएँ शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें मुख्यतः न्यूरोलॉजीए न्यूरो सर्जरीए आंकोलॉजी की सुविधा होगी। दुमकाए पलामू और हजारीबाग में निर्माणाधीन 500 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा कराकर उसे संचालित किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि धनबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की क्षमता 500 बेड से बढ़ाकर 1000 बेड किया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेज को मिलाकर कुल 2000 बेड की वृद्धि होगी। जमशेदपुर स्थित एमजीएम में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 150 और पीजी की सीटें 45 से बढ़ाकर 51 किया जाएगा। धनबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पीजी की सीटें 09 से बढ़ाकर 24 किया जाएगा। डॉण इरफन अंसारी ने

कहा कि रांची के कांके में मेडिको सिटी विकसित होगा। यहां मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मेडिको सिटी में दस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ साथ हेलीपैड की भी व्यवस्था होगी। उनकी सरकार राष्ट्रीय उच्च मार्ग के समीप राज्य में 48 ट्रामा सेंटर बनाने जा रही है। झारखंड की जनता को मुफ्त में दवा देंगे। राज्य में डायल 108 की तर्ज पर दुमका में अलग कॉल सेंटर खोलेंगे। जिससे 300 नए एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस जोड़े जाएंगे। ये 300 बाइक एंबुलेंस होंगे जो दुर्ग पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होंगे। एंबुलेंस सेवा को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके रिस्पांस टाइम को ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट और शहरी क्षेत्र में 25 मिनट करने का लक्ष्य है। राज्य में दुमकाए चाईबासाए हजारीबाग व पलामू में नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। सहिया बहनों को 42000 टैब दे रहे हैं। उस टैब में मेडिकल के सभी सिस्टम होंगे।

विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर में 1 करोड़ की राशि बांटी

चौपारण ०३/०१ (संवाददाता): जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग सचिव पुरुषोत्तम कुमार गोस्वामी के निर्देशन में प्रखंड मुख्यालय सभागार में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन बीडीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में रविवार को किया गया। शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका चोपड़ाए विशिष्ट अतिथि विधायक सह निवेदन समिति सभापति उमाशंकर अकेलाए सांसद प्रतिनिधि मुकुंद सावए थाना प्रभारी स्वप्न कुमार महतोए अधिवक्ता सह पैनल लॉयर मुरली राणाए पीएलवी हरेन्द्र कुमार राणा



ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंच से जिला न्यायिक दंडाधिकारीए विधायक अकेला सहित अन्य ने बारी-बारी से कानूनी जागरूकता से संबंधित जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग कानून और अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण सामाजिक न्याय से वंचित रह

जाते हैं। न्यायालय में शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिलना अभी के समय में बहुत कठिन हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 ;कड में हर नागरिक को सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है। जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित नहीं रह सकता। हर नागरिक को

समान अवसर के साथ-साथ आसानी से न्याय उपलब्ध होना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत केंद्रए राज्य एवं जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितिए उप समिति एवं तहसील विधिक सेवा समिति

का गठन किया गया। जिसके अंतर्गत लोगों को सरकारी खर्च पर वकीलए कोर्ट फीस के लिए खर्चए अभिलेख कागजातों को तैयार करने का खर्चए गवाहों को आने-जाने का खर्चए मुकदमे से संबंधित अन्य जरूरी खर्च कि सुविधाएँ लोगों को प्राप्त है। साथ ही लोग निशुल्क विधिक सेवा पाने का हकदार हैं। जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनको सामाजिक शोषणए बेगारी कराई जाती है। वैसे महिलाएँ एवं बच्चे मानसिक रोगी एवं विकलांग व्यक्तिए जातीय हिंसाए बाढ़ए सूखाए

भूकंप में पीड़ित व्यक्ति औद्योगिक श्रमिकए कारागृहए किशोर मनोचिकित्सक अस्पताल मनो चिकित्सीय परिचर्या अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति ऐसे सभी लोग जिनकी वार्षिक आमदनी एक लाख से कम है। उन्हें निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सके। साथ ही उन्होंने अपने प्रखंड में संचालित सारी योजनाओं को बारे में बताया ताकि लोग जागरूक हो सके। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों के द्वारा लाभुकों को पीएम आवासए पेंशन योजना वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन विकलांगता पेंशन सहित कई लाभकारी योजनाओं से लाभुकों को लाभांवित किए गए।



सेल द्वारा कोलकाता में मूल्य श्रृंखला साझेदार बैठक 2025-26 का आयोजन

कोलकाता ०३/०१ (संवाददाता): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने कोलकाता स्थित होटल हयात रीजेंसी में सेल मूल्य श्रृंखला साझेदार बैठक 2025-26 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेल की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाकर सतत एवं जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को सुदृढ़ करने हेतु सहयोग को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), भिलाई इस्पात संयंत्र; श्री ए के चक्रवर्ती, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र; श्री बी एस पोपली, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), बोकारो इस्पात संयंत्र; श्री सी आर मिश्रा, कार्यपालक निदेशक (ईएमडी), कोलकाता, श्री देवब्रत दत्ता तथा कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), राउरकेला इस्पात संयंत्र, श्री अनिल कुमार मंच पर उपस्थित



थे। इस बैठक में 100 से अधिक उच्च-गुणवत्ता मूल्य श्रृंखला साझेदारों ने भाग लिया। साथ ही सेल की विभिन्न इकाइयों के सामग्री प्रबंधन विभाग के लगभग 50 अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग (ईएमडी) तथा केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) के प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एसईबीआई (स्वच्छ) के दिशानिर्देशों और ईएसजी-संचालित विकास के प्रति सेल

की प्रतिबद्धता के अनुरूप, व्यावसायिक दायित्व एवं सतत प्रतिवेदन (बीआरएसआर), सततता प्रकटीकरण, नैतिक सोर्सिंग प्रथाओं तथा आपूर्तिकर्ता (स्वस्थश्रद्धा) आचार संहिता पर सेल के मूल्य श्रृंखला भागीदारों को अवगत कर शामिल करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ पौधारोपण के साथ किया गया, जो पर्यावरणीय सततता के प्रति सेल की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी, श्री आलोक

वर्मा ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सततता को पूरी मूल्य श्रृंखला की साझा जिम्मेदारी बताया तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में भागीदारों की भूमिका पर बल दिया। श्री अनिल कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि श्री देवब्रत दत्ता ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत की। श्री बी एस पोपली ने मुख्य वक्तव्य दिया तथा बतौर मुख्य अतिथि श्री ए के चक्रवर्ती ने

सततता, जिम्मेदार खरीद, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और आज के गतिशील नियामक और व्यावसायिक वातावरण में मूल्य श्रृंखला भागीदारों से उभरती अपेक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। सततता पहलों, मानव संसाधन मानदंडों तथा आपूर्तिकर्ता आचार संहिता पर प्रस्तुतियाँ क्रमशः महाप्रबंधक (ईएमडी), कोलकाता; सुश्री राखी सेन, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) निगमित कार्यालय), श्री हरि मोहन झा तथा महाप्रबंधक (ईएमडी), सुश्री अजन्ता सेनगुप्ता द्वारा दी गई। इन सत्रों के माध्यम से अनुपालन आवश्यकताओं, प्रतिवेदन ढाँचों तथा सतत मूल्य श्रृंखला प्रबंधन की सर्वोच्च प्रथाओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रस्तुतियों के उपरांत एक खुले मंच चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें कई मूल्य श्रृंखला साझेदारों ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपने

विचार, चिंताएँ एवं सुझाव साझा किए, जिससे विचारों का सार्थक एवं संवादात्मक आदान-प्रदान संभव हुआ। कार्यक्रम के दौरान सेल की सततता एवं सीएसआर यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास एवं समावेशी विकास की दिशा में संगठन की पहलों को दर्शाया गया। कार्यक्रम का समापन राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) श्री टी विनोद द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की मूल्यवान उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए सतत भविष्य के लिए साझेदारी को मजबूत करने हेतु सेल की प्रतिबद्धता को दोहराया। उल्लेखनीय है कि, राउरकेला इस्पात संयंत्र की एक केंद्रीय समिति टीम ने संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय एवं संचालन किया।

स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू होगी, प्रस्ताव को मंजूरी दी



भुवनेश्वर ०३/०१ (संवाददाता): ओडिशा में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की जा रही है। इस योजना के शुरू होने के बाद छात्र मुक्त में स्कूल जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने इस संबंध में विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से स्कूलों

में विद्यार्थियों के ड्रॉप-आउट दर को कम करना है। यह सेवा मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध होगी। स्कूली बच्चे एसी और नॉन-एसी दोनों बसों में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, बस में यात्रा करते समय छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनना और अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। यह योजना उन मार्गों पर लागू की जाएगी जहां स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है।

पिकनिक का माहौल बिगड़ा, दुलुरी पाइन जंगल में दो ग्रुप भिड़े



कंधमाल ०३/०१ (संवाददाता): कंधमाल जिले के डेरिंगबाड़ी के मशहूर दुलुरी पाइन फॉरेस्ट में पिकनिक का माहौल तब बिगड़ गया, जब दो ग्रुपों के बीच झड़प हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना साल 2025 के आखिरी रविवार को हुई, जब इस मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर भारी भीड़ जमा थी। साल के आखिरी रविवार के मौके पर, राज्य और देश के अलग-अलग हिस्सों से टूरिस्ट खूबसूरत माहौल में पिकनिक मनाने के लिए दुलुरी पाइन फॉरेस्ट आए थे। हालांकि, जश्न का माहौल तब खराब हो गया

जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर शराब पी और ज़ोर-ज़ोर से बहस करने लगे। दो ग्रुपों के बीच झड़प हालात तब और बिगड़ गए जब दो ग्रुपों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। झड़प तेजी से बढ़ गई, जिससे पूरे इलाके में डर और अफरा-तफरी फैल गई। चरमदीयों ने बताया कि हिंसा के कारण लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि इस शांत टूरिस्ट जगह पर दहशत फैल गई थी। पुलिस ने दखल दिया, हल्का बल प्रयोग किया पुलिस मौके पर पहुंची और शुरू में हालात को काबू में करने की कोशिश की। हालांकि, बताया

जा रहा है कि उनकी कोशिशें नाकाम रही क्योंकि हिंसा जारी रही। बाद में, पुलिस ने आरोपी लोगों को हिरासत में लिया और भीड़ को तितर-बितर करने और हालात सामान्य करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। हालात काबू में पुलिस की कार्रवाई के बाद, आखिरकार हालात काबू में आ गए और इलाके में शांति बहाल हो गई। इस घटना ने छुट्टियों के मौसम में टूरिस्ट जगहों पर सुरक्षा और अनुशासन को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जिससे सार्वजनिक जगहों पर ऐसी अनुशासनहीनता को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है।

ओडिशा के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग बीजद के एजेंडे में शीर्ष पर

भुवनेश्वर ०३/०१ (संवाददाता): बीजद ने कहा कि ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उसके एजेंडे में शीर्ष पर रहेगी। पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बीजद संसदीय दल की बैठक के बाद राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा ने मीडियाकर्मियों से कहा कि भाजपा ने 2014 के चुनाव घोषणापत्र में ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया थाए लेकिन अब वह इसे भूल गई है।

उन्होंने कहा घ्यदिकेंद्र द्वारा दिए गए किसी भी कारण से ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता हैए तो इसे विशेष फेकस वाला राज्य बनाया जाना चाहिए। पात्रा ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने सांसदों से संसद में ओडिशा और ओडिशा लोगों की मजबूत आवाज बनने को कहा है।

होम गार्ड नौकरियों के लिए 4,000 से अधिक आवेदन



झारसुगुड़ा ०३/०१ (संवाददाता): संबलपुर के हवाई अड्डे पर परीक्षा देते उज्ज्मीदवारों का वायरल वीडियो सामने आने के बाद, ओडिशा में नौकरी के इच्छुक उज्ज्मीदवारों की भारी मांग के बीच रिक्रियों की कमी को एक और घटना ने उजागर किया है। रविवार को झारसुगुड़ा जिले में होम गार्ड के केवल 102 पदों के लिए लिखित परीक्षा में 4,000 से अधिक उज्ज्मीदवार शामिल

हुए। इसके अलावा, कुछ आवेदक स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक होने के बावजूद, उस परीक्षा में शामिल हुए जिसके लिए केवल पांचवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक थी। नियमित रोजगार के अवसरों की कमी के कारण, उज्ज्मीदवारों को कम वेतन वाली और अस्थायी सरकारी नौकरियों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, 102 रिक्रियों

के लिए कुल 4,040 उज्ज्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी। परीक्षा ओडिशा विशेष सशस्त्र पुलिस (ओएसएपी) बटालियन मैदान में आयोजित की गई थी। भर्ती प्रक्रिया के अनुसार, लिखित परीक्षा से 1,010 उज्ज्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा। दोनों चरणों में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद अंतिम चयन किया जाएगा।

सरकारी बस में 40 किलो गांजा, 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार

राउरकेला ०३/०१ (संवाददाता): सरकारी बस में गांजा तस्करी के साथ मिलकर गांजा तस्करी करने के आरोप में सुंदरगढ़ पुलिस ने सरकारी बस के कंडक्टर रुपक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीन गांजा तस्करी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के संबंध में सुंदरगढ़ थाना के डीएसपी सोमनाथ जेना मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सुंदरगढ़ पुलिस ने एक गांजा तस्करी गिरफ्तार का भंडाफेड़ किया है। डीएसपी श्री जेना ने बताया कि राउरकेला जयपुर चलने वाली ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (ओएसआरटीसी) की सरकारी बस के कंडक्टर रुपक मिश्रा सहित 4 गांजा तस्करी को पेडलर को कथित तौर पर गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार

किया। इस मामले में गांजा तस्करी के रूप में आरोपित मोहम्मद सद्दाम मुनवर अली और मोहम्मद तासिब को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 40 किलो गांजा जप्त किया गया। पुलिस ने बताया कि बस कंडक्टर इन गांजा तस्करी के साथ मिलकर बस के माध्यम से गांजा तस्करी करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने छापामारी कर इनको गांजा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस संबंध में पुलिस एनडीपीएस एजेंट के तहत चारों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां इनकी जमानत खारीज होने के कारण सभी को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी बसों के माध्यम से गांजा तस्करी करने के इस मामले में अन्य लोगों

की संलिप्तता का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बणई वन विभाग के अंतर्गत तामड़ा रेंज के रूसीमठ रिजर्व फॉरेस्ट में मोरों के शिकार की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारीयों ने सदलबल छापामारी की। वन विभाग के उड़नदस्ते ने तामड़ा रेंज कांटापाली बीट के कर्मचारियों के साथ मिलकर रूसीमठ रिजर्व फॉरेस्ट से एक मृत नर मोर को जप्त किया। जबकि इस मोर का शिकार करने वाले शिकारी मेसाक मिंज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शिकारी मेसाक का घर सान बड़गांव है। मंगलवार को तामड़ा वन अधिकारी देवाशीष नायक ने शिकारी मेसाक मिंज के खिलाफ वन्यजीव शिकार और न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज कोर्ट चालान कर दिया।

राउरकेला ०३/०१ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में आरएसपी 2030 के लिए रणनीतिक सोच क्षमता को दोगुना करना, लक्ष्य उत्कृष्टता को बनाए रखना शीर्षक से एक कार्यशाला आयोजित की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी (डीआईसी), श्री आलोक वर्मा उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक (खान विकास एवं सीएमएलओ), श्री बी के गिरि, कार्यपालक निदेशक (वर्क्स), श्री विश्व रंजन पलाई, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक (खान, ओजीओएम, सीएमएलओ), श्री एम. पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्य महाप्रबंधकों, विभागाध्यक्षों और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित लगभग 60 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में



भाग लिया। विशेष रूप से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एडमिस्ट्र), श्री विवेक गुप्ता, सत्र के अध्यक्ष हैं। कार्यशाला एक केंद्रित क्षमता निर्माण पहल है जिसका उद्देश्य संगठन को भविष्य के विकास और निरंतर प्रदर्शन उत्कृष्टता के लिए तैयार करना है। सभी को संबोधित करते हुए श्री आलोक वर्मा ने कहा, राउरकेला इस्पात संयंत्र के पास एक महत्वाकांक्षी विकास योजना है, जिसमें उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4.5

एमटीपीए से बढ़ाकर 9.8 एमटीपीए करने का लक्ष्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित रणनीति होना आवश्यक है। उन्होंने प्रतिभागियों से सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने, चर्चाओं में सार्थक रूप से शामिल होने और आरएसपी की दिशा में रचनात्मक योगदान देने का आग्रह किया, जो इस समय सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य

व्यावहारिक रणनीतिक ढांचे और उपकरणों के साथ वरिष्ठ नेतृत्व को लैस करना था, जिससे उन्हें सक्रिय, दीर्घकालिक रणनीति की ओर प्रतिक्रियाशील उत्कृष्टता से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके। प्रतिभागियों को उन क्षेत्रों का निदान करने के लिए निर्देशित किया गया था जहां उनके संबंधित कार्यों को बाधित किया जा सकता है, उत्पादकता की नाजुकता की पहचान करें, और आरएसपी के 2030 ध्येय के साथ संरेखित

एक रणनीतिक अंतर नक्शा बनाने के तरीकों को समझें। कार्यशाला के दौरान विभिन्न सत्रों ने रणनीतिक सोच क्षमताओं को मजबूत करने, लोगों को महत्वपूर्ण क्षमता और उत्पादकता बुनियादी ढांचे के रूप में पहचानने और लाइव सिमुलेशन के माध्यम से एआई और भविष्य के कोशल की खोज करने पर ध्यान केंद्रित किया। कार्यक्रम का एक प्रमुख परिणाम एक संरचित 60-दिवसीय कार्रवाई प्रयोग के साथ एक रणनीतिक अंतर मानचित्र का विकास था, जिसका उद्देश्य अपने महत्वाकांक्षी विकास और प्रदर्शन उद्देश्यों के अनुरूप रणनीतिक नेतृत्व क्षमताओं के निर्माण के लिए आरएसपी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।